[Mr. Speaker]

dra Chaudhuri, Shri Surendranath Dwivedy, Shri A. K. Gopalan, Shri Kashi Ram Gupta, Shri Ansar Harvani, Shri Harish Chandra Heda, Shri Hem Raj, Shri Ajit Prasad Jain, Shri S. Kandappan, Shri Cherian J. Kappen, Shri L. D. Kotoki, Shri Lalit Sen, Shri Harekrushna Mahatab, Shri Jaswantraj Mehta, Shri Bibudhendra Misra, Shri Purushottamdas R. Patel, Shri T. A. Patil, Shri A. V. Raghavan, Shri Raghunath Singh, Chowdhry Ram Sewak, Shri Bhola Raut, Dr. L. M. Singhvi, Shri M. P. Swamy, Shri U. M. Trivedi, Shri Radhelal Vyas, Shri Balkrishna Wasnik, Shri Ram Sewak Yadav, and Shri Asoke K. Sen,

and 15 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The Bill is referred to the Joint Committee.

Shri Hari Vishnu Kamath: This is a Constitution Amendment Bill. The voting must be by division.

Shri Tyagi: It is not an amendment yet.

16.44 hrs.

DISCUSSION *RE*: NEFA ENQUIRY

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, नेफा की घटनाओं ने भारत के मस्तक पर एक ऐसा कलंक का टीका लग या है, जिसे धोने में अभी न जाने कितनी शक्ति और समय लगेगा और कितने बलिदान और दनें होंगे ?

मेरा अपना अनुमान है कि यदि इस सारे घटना चक्र को देश के किसी कोने में बैठकर कोई निष्पक्ष इतिहास लेखक लिख रहा होगा तो उस ने इस नाटक के प्रमुख सूत्रधार तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री और उन की पीठ थपथपाने वाले देश के प्रधान मंत्री को इस के लिये क्षमा नहीं किया होगा ।

भारत की गौरवशाली सैनिक परम्पराओं पर इस का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । जिस सेना की बहादुरी का विश्व में सिक्का माना जाता था, जिस सेना ने न जाने कितने विक्टोरियाक्रास, परमवीर और महावीर चक्र प्राप्त किये, जिस सेना ने काश्मीर, हैदराबाद और गोआ में शत्रु के दांत खट्टे किये, दुर्भाग्य से नेफा की इस घटना से उस सेना को भी बदनाम होना पड़ा ।

नेफा में हुई भगदड़ की जांच रिपोर्ट पर संरक्षण मंत्री श्री चह्वाण ने जो वक्तव्य दिया है उस के आधार पर जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं उस की प्रमुख बातें यह हैं:—

१. सरकार युद्ध के लिये बिल्कुल तैयार नहीं थी ।

२. नेताओं को व्यवहारिकता के धरातल से ऊपर उठ कर आदर्शवाद की हवाओं में उड़ने की आदत अधिक हो गयी थी ।

३. कुछ गिनेचुने असैनिक नेता सेना पर छा गये थे और स्वतन्त्र

निर्णय लेने की बुद्धि उन से छीन सी ली गयी थी। इसीलिये लड़ाई नेफा की पहाड़ियों पर नहीं बल्कि नई दिल्ली के एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठ कर लड़ी गई।

४. पुराने और अनुभवी कुशल सेनाध्यक्षों को ऐसे आड़े वक्त में पदमुक्त किया गया जब कि उनकी सेवाओं से देश को बड़ा लाभ पहुंच सकता था तथा उनके स्थान पर कुछ मनचाहे व्यक्ति किसी भी ढंग से लाए गये।

५. इतनी गंभीर और संकटपूर्ण स्थिति में उच्चतम नेताओं ने वास्तविकता को देश से छिपाया और उस के लिये असत्य तक का सहारा लिया।

६. नेफा में जो कुछ हाथ पैर मारे भी वह भारतीय और विश्व जनमत से विवश होकर मारे गये।

७. इसलिये इस भगदड़ और हार का दोष सेना पर उतना नहीं है जितना कि सरकार पर है।

16.46 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

सरकार की ओर से बरबार यह कहा गया कि हमला अचानक हुआ। पहले इस की कोई सम्भावना नहीं थी लेकिन अभी हाल में नेहरू जी ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि चीन के इरादे १९५० से ही अच्छे नहीं थे। और भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा और जनरल थिमैया की रिपोर्ट क्या है? संरक्षण मंत्री शायद उनसे अच्छी तरह परिचित होंगे। मैं अपनी छोटी सी जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि गंगटोक (सिक्किम) में जो हमारे राजनैतिक प्रतिनिधि थे जो अब शायद इंडोनेशिया में हैं, तीन वर्ष पहले उन्होंने भी इस के सम्बन्ध में संकेत दिया था। जहां तक देश के दूरदर्शी नेताओं और राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है उनमें राजर्षि टंडन, आचार्य कृपालानी, डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी, डाक्टर लोहिया और डाक्टर रघुवीर जैसे व्यक्तियों ने संसद् में और संसद् से बाहर भी चेतावनी दी; उन के अतिरिक्त कुछ विदेशी राजनीतिज्ञों ने भी भारत को इस सम्बन्ध में सावधान किया था। पर सबसे अधिक चेतावनी तो सीमा पर चीनियों द्वारा सड़कों और हवाई अड्डों का बनाया जाना था। हमारी सीमा पर जो सड़कें बन रही थीं और हवाई अड्डे बन रहे थे, क्या वह हमारी आंख खोलने के लिये काफी नहीं थे? आखिर यह सड़कें इसलिये तो बन नहीं रही थीं कि एक मित्र सायंकाल के समय पेकिंग से विमान में बैठ कर वहां आया करेगा और दूसरा दिल्ली से विमान में चढ़ कर वहां जाया करेगा और शाम को उस ठंडी सड़क पर दोनो मित्र हाथ में हाथ डाल कर पंचशील का कनसुर राग अलापा करेंगे। स्पष्ट है कि यह सड़कें किसी और उद्देश्य से बन रही थीं। और फिर हमें तब तो सावधान हो ही जाना चाहिये था जब नौ सिपाहियों की लाशें न जाने कितने दिन बाद हमारे आग्रह पर हमको हवाले की गई। इतने पर भी यह कहना कि हमले की सम्भावना बिल्कुल नहीं थी और हमको पता नहीं था, सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई यह है कि पहले प्रतिरक्षा मंत्री लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। स्थान स्थान पर उन्होंने यह वक्तव्य भी दिये कि लड़ाई अगर कभी होगी तो वह पाकिस्तान से होगी। चीन के साथ तो लड़ाई का कोई सम्बन्ध है ही नहीं। तेजपुर में १० जनवरी १९६० को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि भारत-चीन सीमा विवाद का गुरुत्व इतना नहीं समझा जाना चाहिये कि वह कभी आगे चल कर युद्ध में बदल जायेगा। न केवल अपने देश में वरन् दूसरे देशों में भी, वाशिंगटन में २१

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

नवम्बर को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद अवश्य हैं, हमारे क्षेत्र में भी चीनी घुस आये हैं परन्तु उन के साथ में कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है। यहीं तक नहीं बल्कि आक्रमण से एक महीना पहले तक जब वह अमरीका जा रहे थे तो रास्ते में १८ सितम्बर को लंदन के हवाई अड्डे पर प्रेस-प्रतिनिधियों को वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा नेफा की स्थिति नियन्त्रण में है। कोई गम्भीर स्थिति वहां नहीं है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो मैं भारत छोड़कर कभी विदेश न आता और एक महीने बाद जब हमला हो गया तो आक्रमण होने के अगले ही दिन जब २९ अक्तूबर को दिल्ली के लोगों ने यह चाहा कि हम अपने प्रतिरक्षा मंत्री से यह जानें कि हमारी प्रतिरक्षा की क्या सन्तोषजनक व्यवस्था की गई है। रीगल बिल्डिंग के पास नई दिल्ली में एक सभा हुई। उस सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चीनियों ने १० सितम्बर को ही हमारी सीमा में प्रवेश करने का फैसला कर लिया था, और १८ सितम्बर को एक मास पूर्व लंदन में यह वक्तव्य दिया कि कोई लड़ाई जैसी स्थिति नहीं है। जैसा कि पहले उनके वक्तव्य को मैंने पढ़ कर सुनाया असल में प्रतिरक्षा मंत्री का मन लड़ने का नहीं था। उन की वाणी कुछ बोलती थी और हृदय कुछ बोलता था। एक ऐसे समय में जब कि देश में चारों ओर घबराहट थी, चारों ओर से उलटे समाचार आ रहे थे, प्रतिरक्षा मंत्री अचानक बंगलौर गये। वहां बड़े साहस और घमंड के साथ उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों को मैं आप को पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"India was determined to throw the Chinese out of Indian soil." Addressing Congress workers, Mr. Menon said that while India had no desire to start a war of any magnitude anywhere, it would resist if attacked. 'We will fight to the last man, to the last gun' he declared."

उन्होंने ये शब्द बंगलौर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच कहे। मैं नहीं कह सकता कि यह उन के अपने हृदय की आवाज थी, या बंगलौर के उत्साही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देख कर उन के मुंह से ये शब्द सहसा निकल गये। लेकिन वास्तविकता क्या थी, इस का परिचय तब मिला, जब कि श्री मेनन ने, जिन्होंने बंगलोर में कहा था कि हम आखिरी आदमी और आखिरी हथियार रहने तक लड़ेंगे उनकी हाल ही में प्रकाशित "इंडिया एंड दि चाइनीज इन्वेजन" नाम की अपनी पुस्तक के ३१ वें पृष्ठ पर लिखे तीसरे पैराग्राफ को पढ़ा :

"I want to say this publicly: it has never been the policy of our Government and, I hope it will never be, to do what is called fighting 'to the last man and to the last gun'. The function of any army is not to commit suicide misconceiving it as glory.".

ये भी उन के ही शब्द थे। इसी से उन के हृदय का अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि उसी २१ अक्तूबर की यहां की सार्वजनिक सभा में, अपनी पुस्तक में और कई स्थानों पर दिये गये अपने वक्तव्यों में भी उन्होंने यह कहा है कि लड़ाई के साधनों के लिये गवर्नमेंट ने पैसा बहुत कम दिया है। मैं नहीं कह सकता कि तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री इस बात को कह कर किसी व्यक्ति-विशेष पर लांछन लगाना चाहते थे या अपनी भूलों पर पर्दा डालना चाहते थे। आचार्य कृपालानी ने पीछे जब ऐसी ही कुछ बात कही थी तो तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि आचार्य कृपालानी भी उनमें थे, जो पैसा कम देने के लिये कहते थे। इस के उत्तर में आचार्य कृपालानी ने कहा कि मैं

उन परिस्थिति ों में यह बात कहता था जब तुम "हिन्दी चीनी भाई भाई" कहते थे और जब तुम को पैसा देने का कोई लाभ भी न ीं ा।

लेकिन प्रश्न यह है कि जो पैसा उनको दिया गया, क्या उस पैसे को उन्होंने सुरक्षा के कार्य में पूरा इस्तेमाल किया। अभी तीन दिन पहले श्री कामत, के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि जब से श्री मेनन हमारे देश के प्रतिरक्षा मंत्री हुए, इन पांच सालों में उन को जो पैसा दिया गया, उस में से १,३२,००,००,००० रुपया ऐसा था, जो उन्होंने खर्च न करके सरकार को सधन्यवाद वापस कर दिया।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक ओर उन्होंने यह कहा कि सरकार पूरा पैसा खर्च के लिये नहीं दे रहे थे और दूसरी ओर उन्होने सरकार को पैसा भी वापिस किया।

अपनी इस किताब में उन्होंने फारेन एक्सचेंज की भी चर्चा की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि संरक्षण मंत्री अपना उत्तर देते ए इस प्वाइंट को साफ तौर से बतायें कि इस १,३२,००,००,००० रुपये में विदेशी मुद्रा कितनी थी, जो कि सरकार को वापस की गई है जिस के बारे में भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया था।

मुझे इस समय महाभारत के शल्य की याद आ जाती है, जो बैठा किसी के रथ पर था और विजय किसी दूसरे की चाहता था। मैं नही जानता कि जैनेवा के काफी हाउस में बैठ कर चीन के विदेश मन्त्री, चेन यी, के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे देश में जगह-जगह जाकर उन्होंने किस तरह अपनी ही सीमाओं की रक्षा सम्बन्धी रस्हयों को प्रकट किया। लखनऊ की एक सार्वजनिक सभा में २६ दिसम्बर को तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा, "अगर युद्ध छिड़ गया, तो एक माचिस से लेकर टैंक तक वहां पर भेजने पड़ेंगे।" और जब लड़ाई हुई और हमारे पास साधनों का अभाव दीखा, तो फिर यह बात सत्य साबित हुई।

लेकिन इनसे भी भयंकर २३ अप्रैल को बम्बई में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसके शब्दों को मैं पढ़ कर सुनाता हूं। क्या किसी भी देश का प्रतिरक्षा मन्त्री इतनी गैर ज़िम्मेदारी की बात कर सकता है कि अपनी सेना के रहस्य को सार्वजनिक सभाओं में प्रकट करके शत्रु तक पहुंचाने की कोशिश करे ? लेकिन तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री ने यह भी किया।

श्री त्यागी : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर।

मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर यह है कि मैं आपके सामने विनयपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, शास्त्री जी, जो बातें कह रहे हैं, उनका नेफ़ा एनक्वायरी से, जो मज़मून इस वक्त हमारे सामने है, उससे, कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : सम्बन्ध है। *(Interruptions)*.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There is no point of order.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, अपने घर के रहस्यों को शत्रु को दे देना जिस से वह हमारी धरती का निशंक आक्रमण कर दे त्यागी जी उसका नेफा जांच से सम्बन्ध ही नहीं मान रहे। तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री ने क्या कहा जरा अब सुनिये—

"India does not wish to fight over the Himalayan ranges but if China has any intention of coming down the Himalayan slopes and

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

entering the plains, then we are prepared to give her a warm reception, warmer than she might expect."

इसका तो सीधा ही अभिप्राय यह था कि हिमालय में हम कोई मुकाबला नहीं करेंगे, आप आसानी से कूदते-फांदते आ सकते हैं। यदि इसका अभिप्राय यह होता कि हमने तो शत्रु को चाल में लाने के लिए यह वक्तव्य दिया था, तो उसका परिचय फिर तब मिलता, जब हमने भी वहां पर जम कर दो दो हाथ किये होते या मुकाबला किया होता ? मैं आप को कहना चाहता हूं कि शायद इसी कारण १९ नवम्बर को जब बामडीला का पतन हुआ, तो प्रधान मन्त्री ने दिल्ली रेडियो से बड़ी भारी हुई आवाज में अपनी शुभ-कामना आसाम के निवासियों को भेजी। और शायद वही सब उन बातों की पृष्ठ भूमि भी थी, जिस में---आसाम के माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, वे मेरी बात की साक्षी करेंगे---गौहाटी के सर्कट हाउस में, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां गये, उस समय उनके साथ गये उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने बिना किसी अधिकार के यह कह डाला कि अगर आसाम जाता भी है, तो चला जाने दो, कुछ दिनों बाद हम उसको फिर वापस ले लेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं संरक्षण मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में यह और आवश्यक हो गया है कि यह जो जांच की गई है, उसके अतिरिक्त एक और स्वतन्त्र जांच समिति बिठाई जाये, जो कि इन असैनिक राजनीतिज्ञों की गतिविधियों का निरीक्षण करे और देखे कि यह जो हम को पराजय का मुंह देखना पड़ा, या यह जो हमें चोट लगी, कहीं उसका कारण वे ही तो नहीं थे। मेरा अपना अनुमान यह है कि देश के प्रधान मंत्री ने भी जो उन्हीं लोगों से मिलते-जुलते कुछ वक्तव्य दिये हैं, शायद उनकी जानकारी के स्रोत भी बिल्कुल वही थे। पर अब मैं इस चर्चा को छोड़ कर आगे बढ़ता हूं।

विदेशों से हथियार लेने के सम्बन्ध में जहां उन्होंने कहा कि आत्म रक्षा के लिए हथियार लेना आत्महत्या करने के बराबर है। वहां संरक्षण मन्त्री ने अब कहा है कि हम तैयारियां कर रहे हैं। इससे यह ध्वनि तो स्पष्ट निकलती है कि इससे पहले इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन प्रधान मन्त्री ने २५ नवम्बर, १९५९ को शायद तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री के आधार पर इसी लोक-सभा में जो शब्द कह डाले मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

"But I can tell the House that at no time since our independence have our Defence Forces been in better condition, in finer fettle, and backed by greater industrial production than today. I am not boasting about them, but I am quite confident that our Defence Forces are well capable of looking after our security."

प्रधान मंत्री जो इस प्रकार की गर्वोक्ति भरी बातें कह रहे थे, मेरा अपना अनुमान है कि उनकी जानकारी के सारे आधार भी वही थे।

संरक्षण मन्त्री ने अपने वक्तव्य में उच्च-अधिकारियों की कर्त्तव्यहीनता के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत दिया है। पर ये सारी बातें भी इसीलिए हुईं कि हमारे जो पुराने अनुभवी सेनाधिकारी थे, उनको हटा कर---जबकि हर देश आड़े वक्त में अपने पुराने अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा देकर रखता है---इस प्रकार के व्यक्तियों को मोर्चे पर नियुक्त किया गया, जिनको मोर्चे की शक्ल देखते ही जुकाम और बुखार हो गया और जो दिल्ली के हास्पिटल में आकर पड़ गये। हमारी उस पराजय का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हुआ। पर क्या संरक्षण मंत्री अपने वक्तव्य में बतायेंगे कि जिस व्यक्ति की वजह से हम

को वहां चोट खानी पड़ा, ब्रिटिश सेना की उस व्यक्ति के बारे में क्या रिपोर्ट थी ? कोरिया में जब वह व्यक्ति गया, तो भारतीय सेनाधिकारियों ने उस व्यक्ति के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी और क्या यह सत्य नहीं है कि जब वह व्यक्ति कोर कमांडर बना कर वहां पर रखा गया, तो अपनी दुर्बलता और भय के कारण वह सेना के हैडक्वार्टर को तेजपुर से हटा कर गौहाटी ले आया और उसने यूनीवर्सिटी के होस्टल को इसलिए खाली करा दिया कि सेना का हैडक्वार्टर वहां रखा जायेगा, लेकिन जब ईस्टर्न कमाण्ड को यह सारी बात पता चली, तो उनके अनुरोध पर——मुझे यह पता लगा है——दोबारा हैडक्वार्टर को तेजपुर भेजा गया ?

मैं संरक्षण मन्त्री को यह कहना चाहता हूं कि अनुभव का दुनिया में आज तक कोई विकल्प नहीं हुआ है। अनुभव की बड़े से बड़े शक्तिशाली देश भी बहुत सम्हाल करते हैं। नेफा में हुई हमारी पराजयों में एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अनुभवी अधिकारियों को अपने हाथों से खो दिया था। इसीलिये सुना तो यहां तक गया है कि १४ नवम्बर को, जब प्रधान मन्त्री का जन्म दिन था, उन महाशय ने बधाई का तार दिया और अपने तार में यह भी लिखा कि मैं आपको यह भी सूचना देना चाहता हूं कि बामडीला को कोई खतरा नहीं है। और फिर तीन दिन बाद उसी बामडीला का पतन भी हो गया। प्रधान मन्त्री को रेडियो पर घोषणा करनी पड़ी कि बामडीला का पतन हो गया है।

लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को क्या सज़ा सरकार ने दी ? यह कि सेना से हटा कर एक असैनिक जहाज़ कम्पनी में दस हज़ार रुपये प्रति मास पर उसको नियुक्त कर दिया। क्या सरकार इस प्रकार सेना में अनुशासन रख सकेगी ?

संरक्षण मन्त्री ने अपने वक्तव्य में सैनिक गुप्तचर विभाग को गतिविधियों पर बहुत बल दिया है। अपने सारे वक्तव्य में उन्होंने किसी बात पर अधिक बल दिया है, तो मिलीटरी इन्टेलिजेंस पर, संरक्षण मन्त्री के वक्तव्य में इस विषय के अतिरिक्त किसी एक विषय पर पांच पैराग्राफ्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध-काल में गुप्तचर विभाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे महायुद्ध में यही गुप्तचर विभाग था, जिस ने जर्मनी से इंग्लैण्ड पर आने वाली विपत्ति के मुंह को रूस की ओर मोड़ दिया था। अगर कहीं हमारा गुप्तचर विभाग पूर्ण सतर्क होता, तो जिस प्रकार से पिछले आठ दस सालों से चीन के गुप्तचर विभाग ने . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और समय लेना चाहते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो कल माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद।

---

17 hrs.

LANGUAGE USED ON AIR*

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, ९ सितम्बर को आल इंडिया रेडियो की जो मौजूदा पालिसी है उसके मुताल्लिक जो सवाल आया था मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सरकार ने ९ सितम्बर को जो जवाब दिया था वही जवाब उसने २४ अप्रैल को दिया था। भाई भक्त दर्शन जी ने जो सवाल चार महीने पहले पूछा था उसके जवाब में सरकार ने कहा था कि इसके लिये कोई तारीख नहीं बतलाई जा सकती न कोई डेडलाइन कायम की जा सकती है। वही सवाल मैंने ९ सितम्बर को पूछा तो सरकार ने यह कहा कि हम अमल कर रहे हैं लेकिन कोई डेडलाइन सरकार तय नहीं कर सकती। चार महीने के बाद सरकार वहीं की वहीं है। हम लोग यह ख्याल करते थे कि सरकार वहां से बहुत आगे बढ़ेगी लेकिन चार महीने बाद

*Half-an-hour Discussion.